



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली बुधवार, मार्च 10, 1976/फाल्गुन 20, 1897

No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1976/PHALGUNA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th March 1976

No. F.2-17/76-AC.—Government have been considering for sometime past the measures to be taken for meeting the consumption needs of small farmers, landless labourers and rural artisans, consequent on the measures recently taken by State Governments for moratorium, discharge and scaling down of debts from the non-institutional sources. It has now been decided to set up an Expert Committee consisting of the following persons:

Chairman

1. Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission, New Delhi.

Members

2. Shri N. C. Sen Gupta, Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Shri K. S. Narang, Secretary, Deptt. of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.
4. Shri I. J. Naidu, Secretary, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.
5. Dr. C. D. Doley, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.

6. Shri G. V. K. Rao, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.
7. Shri B. R. Gupta, Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.
8. Shri B. B. Tandon, Secretary and Administrator, 20-Point Programme, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
9. Shri V. M. Bhide, Chairman and Managing Director, Bank of Maharashtra, Poona.

Member-Secretary

10. Shri K. P. A. Menon, Joint Secretary, Deptt. of Banking, New Delhi.

One or two members may also be coopted, if considered necessary.

2. The terms of reference of this Committee will be as follows:

- (i) To study the impact of the moratorium, discharge and scaling down of rural indebtedness of the small/marginal farmers, landless labourers and rural artisans so far as their genuine and inescapable consumption credit needs are concerned.
- (ii) To inquire into the purpose for which such consumption credits were availed of.
- (iii) To assess broadly the credit gap in respect of consumption loans consequent on these measures.
- (iv) To review the present position of availability of consumption credit to such people from institutional sources.
- (v) To make recommendations as to the purposes for and the agencies from which such consumption loans are to be provided.
- (vi) To make recommendations on any matter incidental to the terms of reference, as the Committee may consider necessary.

3. The Committee will start functioning with immediate effect and will submit its report by the 31st March, 1976.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, all the Ministries/Departments of the Govt. of India, the Planning Commission, the State Governments and the Governments/Administrations of Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary dated the 10th March, 1976 for general information.

N. C. SEN GUPTA, Secy.

वित्त संचाय

(बैंकिंग विभाग)

संफला

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1976

सं० एक० 2-17/76-ए० सी०-—गैर संचायन स्त्रियों से लिये गये ऋणों के स्थान, भागी और न्यूनीकरण के लिए हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के परिणाम-स्वरूप छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों की उपभोग की आवश्यकताओं

को पूरा करने के उपायों पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी । अब यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की एक विशेष समिति बनाई जाय :—

1. श्री बी० शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग, अध्यक्ष
नई दिल्ली
2. श्री एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव, बैंकिंग विभाग, सदस्य
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
3. श्री के० एस० नारंग, सचिव, कृषि विभाग, सदस्य
कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री आई० जे० नायडू, सचिव, ग्रामीण विकास सदस्य
विभाग, कृषि और सिंचाई विभाग, नई दिल्ली
5. डा० सी० डी० दाते, कार्यकारी निदेशक, भारतीय सदस्य
रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई
6. श्री जी० वी० के० राव, मुख्य सचिव, कर्नाटक सदस्य
राज्य, बंगलौर
7. श्री बी० आर० गुप्ता, मुख्य सचिव, पश्चिम सदस्य
बंगाल सरकार, कलकत्ता
8. श्री बी० वी० टण्डन, सचिव तथा प्रशासक सदस्य
20 सूती कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
9. श्री बी० एम० मिडे, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक सदस्य
बैंक आफ महाराष्ट्र, पुणे
10. श्री के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव, बैंकिंग सदस्य-सचिव
विभाग, नई दिल्ली

यदि आवश्यक समझा गया तो एक या दो सदस्यों को भी सहयोजित किया जा सकता है।

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

- (1) छोटे/सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों की ग्रामीण कर्जदारी के स्थगन, माफी और न्यूनीकरण के प्रभावों का उस सीमा तक अध्ययन करना जहाँ तक उनकी वास्तविक और अपरिहार्य उपभोग ऋण की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है।
- (2) उन प्रयोजनों की जांच करना जिनके लिए ऐसे उपभोग ऋण लिये जाते हैं।
- (3) इन उपायों के परिणामस्वरूप उपभोग ऋणों के सम्बन्ध में ऋण के अंतर का मोटे तौर पर मूल्यांकन करना।
- (4) इन व्यक्तियों को संस्थागत स्रोतों से उपभोग ऋण की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना।
- (5) उन प्रयोजनों तथा अभिकरणों के बारे में सिफारिशें करना जिनके लिए अथवा जिनके माध्यम से इन उपभोग ऋणों की व्यवस्था की जानी है।

(6) विचारणीय विषयों के ऐसे किसी आनुषंगी मामले के बारे में सिफारिशें देना जिन्हें समिति आवश्यक समझे ।

3. समिति तत्काल अपना काम आरम्भ करेगी तथा 31 मार्च, 1976 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासकों को भेजी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प 10 मार्च, 1976 के भारत के आसाधारण राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय ।

एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव ।